- 19th Year
- Issue: 331
- 16.04.2026 (THURSDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

बंगाल में अमित शाह की टीएमसी को सीधी चेतावनी, पांच मई के बाद गुंडों को उल्टा लटका देंगे

कोलकाता १५/०४ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उज़री बंगाल में अपने चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भ्रष्टाचार के जरिए जनता से कथित तौर पर लूटा गया एक-एक रुपया वापस लेगी। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले लगातार रैलियों में बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर बेदाग रहा है और मतदाताओं से राज्य में भाजपा को सज़ा में लाने का आग्रह किया। जलपाईगुड़ी के राजगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी का सज़ा से हटना अब सिर्फ समय की बात है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा उज़री बंगाल से सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करेगी और टीएमसी नेतृत्व पर जनता के धन की हेराफेरी का आरोप लगाया। उन्होंने भीड़ से कहा कि मोदी ने गुजरात पर 12 साल शासन किया और केंद्र में अगले 12 साल सज़ा में हैं; फिर भी उन पर एक पैसे के भ्रष्टाचार का भी कोई आरोप नहीं लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सज़ा में आने के बाद तृणमूल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले में 300 करोड़ रुपये हड़पे और उज़र बंगाल के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत बाढ़ राहत कोष से 100 करोड़ रुपये

चुराए। शाह ने कहा कि उज़र बंगाल तीन टी के लिए जाना जाता है-टी (चाय), टिंबर (लकड़ी) और टूरिज्म (पर्यटन)। लेकिन ममता बनर्जी ने इसमें एक चौथा टी जोड़ दिया है-भाजपा कार्यकर्ताओं के टीअर्स (आंसू), जिन्होंने तृणमूल के गुंडों के हाथों असहनीय पीड़ा झेली है। अलीपुरदुआर जिले के फलाकाटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने फलाकाटा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक और भाजपा के उज़्मीदवार दीपक बर्मन पर मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा किए गए हमले का जिक्र किया। शाह ने कहा कि मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि आपके गुंडे उन्हें (बर्मन को) डरा नहीं सकते, वह भाजपा कार्यकर्ता हैं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि पांच मई (मतगणना के एक दिन बाद) के बाद कोई भी आप पर उंगली तक नहीं उठा सकता।

शाह ने कहा कि मैं तृणमूल के गुंडों को सलाह देता हूं कि वे 23 अप्रैल को, यानी चुनाव के दिन, घर पर ही रहें, वरना पांच मई के बाद हम आपको उल्टा लटका देंगे। घुसपैठिया मुक्त उज़र बंगाल की वकालत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कि जिसने भारत में नज़्सलवाद को समाप्त किया और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया, अब बंगाल और अन्य जगहों पर घुसपैठियों का पता लगाएगी और उन्हें बाहर निकालेगी। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन बिहार में भाजपा के मुज़्यमंत्री ने शपथ ली है। ओडिशा में हमारी सरकार बन चुकी है। बंगाल में भाजपा को चुनिए और अंग-बंग-कलिंग की पवित्र त्रिमूर्ति पर कमल (भाजपा का चुनाव चिह्न) खिल उठेगा।

भाजपा के सम्राट चौधरी ने बिहार के नए सीएम के तौर पर शपथ ली

पटना १५/०४ (संवाददाता): बिहार की सियासत में आज एक नए युग का आगाज़ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार के 21वें मुज़्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में करीब दो दशकों से चले आ रहे नीतीश कुमार शासन% का औपचारिक अंत हो गया है। राजभवन के ऐतिहासिक प्रांगण में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

छ्ठ के मुखिया नीतीश कुमार, जो अब राज्यसभा सांसद हैं, ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट भंग करने के बाद मुज़्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पिछली सरकार में, चौधरी उपमुज़्यमंत्री थे और उनके पास गृह मंत्रालय जैसा अहम विभाग था, जिससे वे प्रशासन में एक महत्वपूर्ण हस्ती बन गए थे।

चौधरी, जो 2017 में छ्ठ्ठक में शामिल हुए थे, मंगलवार को छ्ठ्ठक विधायक दल के नेता चुने गए थे। बिहार की जटिल राजनीतिक तस्वीर में उनके मुज़्यमंत्री बनने का जातिगत महत्व भी है। चौधरी प्रभावशाली कोइरी समुदाय से मुज़्यमंत्री पद संभालने वाले केवल दूसरे नेता बन गए हैं। पहले नेता सतीश प्रसाद सिंह थे, जिनका कार्यकाल 1968 में केवल पाँच दिनों का रहा था, जब कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद उनकी गठबंधन सरकार गिर गई थी।

पश्चिम बंगाल में विकास नहीं, सिर्फ विनाश हुआ है-राजनाथ सिंह

कोलकाता १५/०४ (संवाददाता): रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पिछले पंद्रह वर्षों में पश्चिम बंगाल में विकास की जगह विनाश ही देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सिंह ने दक्षिण दिनाजपुर जिले में एक रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी, जो जनता के मजबूत समर्थन को दर्शाती है। सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ज़्या कानून और संविधान ममता की इच्छा के अनुसार चलने चाहिए? पंद्रह साल बीत गए, फिर भी विकास की जगह बंगाल में विनाश ही देखने को मिला है - वोट बैंक की राजनीति तक सिमट गया है, जहां धर्म के आधार पर लाभ बांटे जाते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि उज़री बंगाल में विकास के लिए केवल 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि मदरसों को विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस असंतुलन ने आज के युवाओं को संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है। इससे पहले, 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज़र बंगाल के खिलाफ कथित भेदभाव और राज्य सरकार की बजट प्राथमिकताओं का मुद्दा उठाया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार पिछले 15 वर्षों का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि टीएमसी अपने 15 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब देने में असमर्थ है, ज़्योंकि उसने वास्तविक कार्य करने के बजाय केवल अनैतिक कृत्य किए हैं, तो वह भला किस बात पर आपको जवाब दे सकती है? प्रधानमंत्री ने बजट आवंटन में उज़र बंगाल के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मदरसों के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि उज़र बंगाल के विकास की उपेक्षा की गई।

विविध समाचार

महिला आरक्षण का समर्थन, पर तरीके पर ऐतराज, मल्लिकार्जुन खरगे बोले-यह राजनीतिक धोखा है

नयी दिल्ली १५/०४ (संवाददाता): विपक्ष की बैठक के तुरंत बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को कहा कि विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सरकार द्वारा विधेयक लाने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित है। इंडिया ज़्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम सभी महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं। लेकिन जिस तरीके से इसे पेश किया गया है, उस पर हमें आपज़ि है। यह राजनीतिक रूप से प्रेरित है। विपक्षी दलों को दबाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। हालांकि हमने महिला आरक्षण विधेयक का लगातार समर्थन किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले के संशोधनों को लागू किया जाए। वे परिसीमन को लेकर कुछ चालें चल रहे हैं।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम सभी दलों को संसद में एकजुट होकर लड़ना चाहिए। हम इस विधेयक का विरोध

करेंगे, लेकिन हम (महिलाओं के लिए) आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं।

जिस तरह से उन्होंने विधेयक में परिसीमन को शामिल किया है, उन्होंने जनगणना भी नहीं कराई है। संविधान की सभी शक्तियां कार्यपालिका द्वारा हथियाई जा रही हैं। ज्यादातर, जो शक्तियां संस्थाओं, संसद के पास होनी चाहिए, वे उन्हें इसलिए दी गई हैं ताकि वे किसी भी समय परिसीमन बदल सकें...वे असम और जज़्मू-कश्मीर में पहले ही हमें धोखा दे चुके हैं।

आईयूएमएल सांसद ई. टी. मोहमद बशीर ने कहा कि हम परिसीमन विधेयक का विरोध कर रहे हैं ज़्योंकि यह वास्तव में एक जाल है। वे 2023 में भी आरक्षण दे सकते थे, और हम अब भी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन साथ ही, यह संवैधानिक संशोधन एक खतरनाक कदम है। हमने इसका (परिसीमन का) पुरजोर विरोध करने का फैसला किया है ज़्योंकि यह न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। आरएसपी सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि परिसीमन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के ज़रिए अनुच्छेद 81 के खंड 3 में संशोधन किया जा रहा है, जिससे एक नया प्रावधान जोड़ा जा रहा है कि संसद कानून बनाएगी और जनगणना व जनसंज़्या का निर्धारण करेगी। इसका मतलब है कि सरकार साधारण बहुमत से ही पूरे देश को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। उज़र भारत में सीटों की संज़्या में भारी वृद्धि होगी, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों में सीटों की संज़्या में कमी आएगी ज़्योंकि उन्होंने भारत सरकार के जनसंज़्या नियंत्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से लागू किया है। यह लोकतंत्र विरोधी है। हम उस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करते हैं जिसके तहत परिसीमन किया जाएगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है और यह परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार संवैधानिक संशोधनों और मौजूदा ढांचे में बदलाव के माध्यम से 2029 के आम चुनावों से पहले इस आरक्षण को लागू करने पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार के प्रस्ताव में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है, जिसमें से 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जाएंगी।

ईडी का शिकंजा! शिकोहपुर जमीन घोटाले में रोबर्ट वाड्रा को कोर्ट का समन

नयी दिल्ली १५/०४ (संवाददाता): बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के शिकोहपुर में विवादित जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोत्रा ने वाड्रा और अन्य आरोपियों को 16 मई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। विस्तृत आदेश का इंतजार है। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल जुलाई में आरोपपत्र दाखिल किया था, जो किसी भी जांच एजेंसी द्वारा 57 वर्षीय वाड्रा के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोपपत्र दाखिल करने का पहला मामला था। केंद्रीय एजेंसी ने अपनी जांच के तहत अप्रैल 2025 में वाड्रा से तीन दिनों तक पूछताछ की थी।

यह पहली बार था जब किसी जांच एजेंसी ने रॉबर्ट वाद्रा (57) के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। अप्रैल 2025 में, ईडी ने वाद्रा से लगातार तीन दिन तक पूछताछ

की थी। वाद्रा के खिलाफ जांच हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर-शिकोहपुर (वर्तमान सेज़्टर 83) में हुए एक भूमि सौदे से जुड़ी है। यह सौदा फरवरी 2008 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा किया गया था, जिसमें वाद्रा पहले निदेशक थे। इस सौदे के तहत कंपनी ने शिकोहपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। उस समय हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी।

चार साल बाद, सितंबर 2012 में कंपनी ने वह जमीन रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी। अज़्टूबर 2012 में यह सौदा विवादों में घिर गया, जब उस समय भूमि समेकन और भूमि अभिलेख के महानिदेशक-सह-पंजीकरण महानिरीक्षक के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने लेनदेन को राज्य समेकन अधिनियम और कुछ संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करार देते हुए 'ज़्यूटेशन' रद्द कर दी। वाद्रा ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया और इस मामले को अपने और अपने परिवार के खिलाफ ''राजनीतिक प्रतिशोध'' बताया। ईडी वाद्रा से जुड़े दो अन्य मामलों की भी जांच कर रही है, जिनमें ब्रिटेन में रह रहे हथियार सलाहकार संजय भंडारी के खिलाफ एक मामला और राजस्थान के बीकानेर में जमीन का सौदा शामिल है।

परिसीमन पर राहुल गांधी का हमला, बोले-ओबीसी, दलितों की हिस्सा चोरी कर रहे पीएम मोदी

नयी दिल्ली १५/०४ (संवाददाता): केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा सीटों की संज़्या बढ़ाकर 850 करने और 2026 से पहले की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति देने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखे जाने के मद्देनजर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलित और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधित्व का हिस्सा छीनने नहीं देगी और इसे एनडीए का राष्ट्र-विरोधी कदम बताया।

ड्ड पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि उनकी कांग्रेस महिला आरक्षण का स्पष्ट रूप से समर्थन करती है, लेकिन सरकार को परिसीमन केवल 2026 की जनगणना के आधार

पर ही करना चाहिए, जो वर्तमान में चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का कोई भी कानून लाने से पहले जाति जनगणना को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जो प्रस्ताव पेश कर रही है, उसका महिला आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। यह संशोधन परिसीमन और हेरफेर के ज़रिए सज़ा हथियाने का प्रयास है। जाति जनगणना के आंकड़ों को नज़रअंदाज़ करके हम ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों की 'हिस्सा चोरी' बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दक्षिणी, उज़र पूर्वी, उज़र पश्चिमी और छोटे राज्यों के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे।

गांधी ने दावा किया कि भाजपा पिछड़े समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती, और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस जाति जनगणना से डरते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर गंभीर है, तो उसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना होगा, जिसे संसद ने 2023 में पहले ही पारित कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रविरोधी गतिविधि है। प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं और पिछड़े समुदायों का हिस्सा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मनमर्जी से परिसीमन चाहते हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

महिला विधायकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023, लोकसभा में परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। सरकार 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण को लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए वह 2023 के अधिनियम में संशोधन और परिसीमन प्रक्रिया को 2027 की जनगणना से अलग करने हेतु संवैधानिक संशोधन ला रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने सदन में सीटों की संज़्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से 815 सीटें राज्यों के लिए और शेष 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं।

पहले चरण के लिए 2407 कंपनियां तैनात, चप्पे-चप्पे पर होग ैकेंद्रीय बलों की नजर

कोलकाता १५/०४ (संवाददाता): भारत निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2,407 टुकड़ियां तैनात करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि सबसे अधिक बल मुर्शिदाबाद जिले में तैनात किए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि मतगणना चार मई को होगी। अधिकारी ने बताया कि मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक 316 टुकड़ियां तैनात की जाएंगी, जिनमें 240 मुर्शिदाबाद पुलिस जिले और 76 जंगीपुर

में होंगी। हाल के वर्षों में मुर्शिदाबाद में कई हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिनमें वज़्फ अधिनियम को लेकर विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी झड़पें और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) आंदोलन के दौरान अशांति शामिल हैं। अधिकारी ने कहा, ''पहले चरण में केंद्रीय बलों की कुल 2,407 टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं।मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान करने का अवसर मिले, इसके लिए विस्तृत आकलन के बाद यह तैनाती की गई है।'' उन्होंने बताया कि पूर्व मेदिनीपुर जिले में दूसरी सबसे अधिक 273 टुकड़ियां तैनात की जाएंगी। यह जिला राजनीतिक रूप से अहम नंदीग्राम सीट के कारण विशेष निगरानी में है, जहां प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में हैं। आयोग ने उज़र दिनाजपुर को दो पुलिस जिलों में बांटा है, जहां इस्लामपुर में 61 और रायगंज में 71 टुकड़ियां तैनात की जाएंगी।अन्य प्रमुख तैनातियों में आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय में 125 और सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय में 44 टुकड़ियां शामिल हैं। उज़र बंगाल के दार्जिलिंग में 61, कलिज़्पोंग में 21, जलपाईगुड़ी में 92 और अलीपुरद्वार में 77 टुकड़ियां तैनात की जाएंगी। पहले चरण के चुनाव में दार्जिलिंग, कलिज़्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उज़र दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा समेत आठ उज़र बंगाल जिलों में मतदान होगा। इसके अलावा मुर्शिदाबाद और पश्चिमी जिलों झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा में भी मतदान कराया जाएगा।

इस चरण में पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम में भी चुनाव होंगे। राज्य के कई इलाकों में केंद्रीय बल पहले ही तैनात किए जा चुके हैं और मतदाताओं में विश्वास जगाने के लिए 'रूट मार्च' किए जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा, ''हम स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

नारी शक्ति एक्ट पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बोलीं-पीएम मोदी का सराहनीय प्रयास

नयी दिल्ली १५/०४ (संवाददाता): भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कानून विधायी निकायों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके संवैधानिक ढांचे को मजबूत करेगा। पत्र में लिखा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऐतिहासिक कार्यान्वयन की पहल के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यह ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन विधायी निकायों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी को सुनिश्चित करके भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। पाटिल ने कहा कि पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने समान

अवसर सुनिश्चित करके महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन किया। उन्होंने इस प्रयास में योगदान देने वाले सभी हितधारकों की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने के प्रयासों को तेज कर दिया है और इसे विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार बताया है। उन्होंने हाल ही में नारी शक्ति को पत्र लिखकर इस बहुप्रतीक्षित विधेयक पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कानून बनाने वाली संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। संसद के आगामी सत्र से पहले, मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के सदन के नेताओं को पत्र लिखकर महिला आरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन का समर्थन करने का अनुरोध किया।

यह कदम संसद के एक महत्वपूर्ण सत्र से ठीक पहले उठाया गया है, जिसके दौरान सरकार से उज़्मीद की जा रही है कि वह कानून से जुड़े संवैधानिक संशोधन को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले सम्राट चौधरी को बधाई दी

नयी दिल्ली १५/०४ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुज़्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले सम्राट चौधरी को बधाई दी है। उन्होंने नीतीश कुमार का स्थान लिया है। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में विश्वास व्यक्त किया कि चौधरी की ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे और उनके नेतृत्व में बिहार सर्वांगीण विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को बिहार के उपमुज़्यमंत्री नियुक्त होने पर शुभकामनाएं दीं। एक अलग पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जमीनी स्तर पर उनका अनुभव और जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बिहार के विकास को नई दिशा और गति प्रदान करेगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण के नए मानक स्थापित

करेगा। सम्राट चौधरी ने 31 जनवरी को पटना स्थित बिहार के राज्यपाल आवास लोक भवन में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन द्वारा दिलाई गई शपथ ली। 57 वर्षीय चौधरी, नीतीश कुमार के एक दशक के कार्यकाल के बाद इस्तीफे और राज्यसभा में शामिल होने के निर्णय के बाद बिहार के पहले भारतीय जनता पार्टी के मुज़्यमंत्री बने।चौधरी की नियुक्ति बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो नीतीश कुमार के सुशासन के युग का अंत करती है और राज्य में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के लिए एक नए चरण का संकेत देती है। चौधरी का राजनीतिक करियर 1990 के दशक में राष्ट्रीय जनता दल से शुरू हुआ था, जिसके बाद वे 2018 में भाजपा में शामिल हुए। चौधरी के साथ-साथ, जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता और बिहार के विज़ मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और पार्टी नेता विजय कुमार चौधरी ने भी उसी दिन बिहार के उपमुज़्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने में मददगार है अरोमाथेरेपी

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिजिकल हेल्थ खराब होने के साथ ही मेंटल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ रहा है। हर दूसरा बंदा काम के बोझ के तले इतना दब गया है कि उसे अपने लिए टाइम ही नही है। तनाव के कारण एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी दिक्कत होने लगी है। लोगों की नींद प्रभावित हो रही है, फोकस करने में परेशानी आती है। अगर आप भी इस तरह की परेशानी होती है तो आप मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए अरोमाथेरेपी का सहारा ले सकते हैं।

क्या होती है अरोमाथेरेपी

अरोमाथेरेपी जैसा की इसके नाम से मालूम चल रहा है अरोमा मतलब खुशबू और थेरेपी मतलब इलाज,खुशबू की मदद से इलाज करने को ही हम अरोमाथेरेपी कहते हैं । यह मानसिक तनाव का इलाज करने का सबसे कारगर तरीका है। एसेंशियल ऑयल्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,यह तेल पौधों,जड़ी बूटियों फूलों,पंखुड़ियों जैसी चीजो से निकाले जाते हैं।

मेंटल हेल्थ को कैसे बूस्ट करता है अरोमाथेरेपी

एक्सपर्ट के मुताबिक लैवेंडर कैमोमाइल जैसे एसेंशियल ऑयल्स में शांत करने वाले गुण होते हैं जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं,इससे बेहतर नींद को बढ़ावा मिलता है और जब आप सुकून भरी नींद सोते हैं तो इससे मस्तिष्क के सेल्स रिपेयर होते हैं । एसेंशियल ऑयल्स की खुशबू लेने से कोर्टिसोल का स्तर कम हो सकता है,जो तनाव के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है,जब आपका कोर्टिसोल हार्मोनकम होता है तो आपको सुकून भरी नींद आती है इससे मेंटल हेल्थ बूस्ट होता है। एसेंशियल ऑयल्स मूड पर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं,अवसाद की भावनाओं को कम कर देवदार की लकड़ी और चंदन जैसी सुगंध गहरी, अधिक आरामदायक नींद चक्र को बढ़ावा देकर नींद की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। क्लैरी सेज जैसे एसेंशियल ऑयल नींद को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं जिससे नींद का पैटर्न सही हो जाता है। अच्छी खुशबू वाला कमरा एक शांत और आरामदायक वातावरण बनाता है जिससे आराम करना और नींद आना आसान हो जाता है।

किडनी की बीमारी में आपका शरीर आपको देता है ये संकेत

स्किन और नाखूनों से ये दिखाई देता है कि हमारी किडनी में किस तरह की बीमारी होने जा रही है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किडनी के लक्षण काफी गंभीर हो सकते हैं।

हमारा शरीर आने वाले हर खतरे का संकेत पहले से ही देने लगता है। शरीर में अगर कोई बड़ी समस्या होने वाली है तो उससे पहले छोटी-छोटी चीज़ों से हमें कुछ न कुछ संकेत मिलते रहते हैं। शरीर का कोई भी बड़ा ऑर्गेन खराब हो रहा हो तो कई बार हमें स्किन और बालों के जरिए भी उसके संकेत मिलने लगते हैं। ऐसा ही किडनी की बीमारी के साथ भी होता है। किडनी की बीमारी होने से पहले स्किन पर कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। यहां सिर्फ बालों का झड़ना या फिर हेयर लाइन शुरू होते ही पलेकी स्किन नहीं बल्कि नाखूनों, पैरों, हाथों आदि पर भी असर दिखता है और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं तो आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। पर आखिर कौन से संकेत है जो साफ दिखाई देते हैं।

किडनी की बीमारी के समय शरीर में होती है ये समस्या

स्किन, बाल और नाखून हमारी सेहत को लेकर बहुत ही जरूरी संकेत देते हैं। कोई भी छुपी हुई बीमारी जैसे मालन्यूट्रीशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ओवरडोज, दवाओं का असर या बीमारी आदि के संकेत इन दोनों से मिल जाते हैं। जिन लोगों को किडनी की बीमारी या किडनी फेलियर का रिस्क होता है उन्हें जिंक, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डजैसे मिनरल्स दिए जाते हैं। जिन मरीज़ों को डायलेसिस की जरूरत होती है उन्हें इन मिनरल्स की कमी के लिए रीनल विटामिन्स दिए जाते हैं जिनमें विटामिन बकॉम्प्लेक्स के हाई लेवल होते हैं। कैल्शियम और आयरन को ब्लड लेवल में मॉनिटर किया जाता है और अगर ये लेवल कम होते हैं तो सप्लिमेंट्स उसी हिसाब से दिए जाते हैं।

किडनी की बीमारी के कारण स्किन पर दिखते हैं ये असर

किडनी की बीमारी के कारण शरीर में टॉक्सिन्स काफी बढ़ जाते हैं और इसके कारण स्किन में नाइट्रोजन भी बढ़ जाता है। स्किन बहुत ड्राई, खुजली वाली हो जाती है। इसी के साथ, स्किन में क्रैक्स, स्केल्स आदि बनने लगते हैं। स्किन काफी पतली हो जाती है और बहुत आसानी से स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं जो कच्चे होते हैं और खुजली वाले भी होते हैं। इनमें आसानी से ब्लीडिंग होने लगती है। स्किन ज्यादा सफेद दिखने लगती है और इसका रंग भी ग्रे, ब्लू, पर्पल या येलो शेड का हो जाता है। सिस्ट्स और स्पॉट्स भी दिख सकते हैं।

हाथ और पैरों में आ जाती है बहुत ज्यादा सूजन

हाथों और पैरों में सूजन, चेहरे में सूजन, ऐड़ियों में सूजन आना बहुत ही आम लक्षण है जिसे लेकर आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। शरीर से टॉक्सिन्स ठीक तरह से बाहर न निकल पाने के कारण ये होता है और आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि ऐसा लक्षण गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है इसलिए डॉक्टर से सलाह लें।

किडनी की बीमारी के कारण नाखूनों पर दिखते हैं ये असर

नाखूनों पर भी किडनी की बीमारी का असर साफ दिखाई देता है। सफेद बैंड्स या स्पॉट्स नाखूनों पर बनने लगते हैं और ये कमजोर, कच्चे और फ्लेकी हो जाते हैं। अक्सर ऐसे नाखूनों के बीच में लाइन बनने लगती है। हमारे नाखून कई और बीमारियों के संकेत भी देते हैं और ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे कोई भी लक्षण के दिखने पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

स्किन पर दाने और रैशेज

जैसा कि हम पहले बता चुके है कि किडनी की बीमारी के कारण शरीर में टॉक्सिन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और ये रैशेज, बंप्स, ब्लीडिंग वाली स्ट्रेचमार्क्स आदि का कारण बनता है ऐसे में आप शरीर में कई तरह के मिनरल्स आदि का टेस्ट करवा सकते हैं। ये सारे लक्षण किसी अन्य वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ किडनी के कारण हों। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो एक्सपर्ट की सलाह लेना ही किसी गंभीर रोग से मुक्ति का अच्छा कारण हो सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न दिखाएं और डॉक्टर से सलाह लेते रहें।

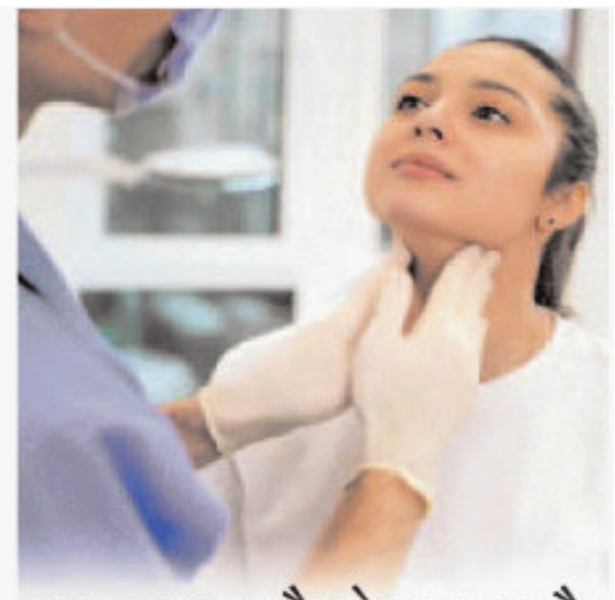

थायराइड कैसे करता है हार्ट हेल्थ को प्रभावित

आजकल थायराइड की बीमारी काफी आम हो चुकी है। थायराइड रोग वह स्थिति है जिसमें थायराइड ग्लैंड शरीर की जरूरत से कम या अधिक हार्मोन का निर्माण करने लगता है जिसके कारण कई सारी समस्याएं पैदा होती है। थायराइड के कारण जहां मोटापा हेयर फॉल , जोड़ों में दर्द जैसी समस्या होती है वहीं यह दिल की सेहत को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की है। आइए जानते हैं थायराइड कैसे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है।

कैसे करता है हार्ट हेल्थ को प्रभावित

एक्सपर्ट बताती हैं की दोनों ही थायराइड हार्ट हेल्थ को प्रभावित करता है। हाइपोथायरायडिज्म की बात करें तो इसमें थायराइड हार्मोन का लेवल शरीर में कम हो जाता है,इससे थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम होने लगता है,इससे मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है,इससे दिल को नुकसान हो सकता है जैसे इससे हार्ट रेट स्लो हो जाता है,इससे आपको ब्रेडीकार्डिया की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है,इसके कारण हृदय का फैलाव हो सकता है। इससे दिल का दौरा पड़ सकता है थायराइड बढ़ने से हार्ट की धमनियां संकरी होने लगती है,इससे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है,लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहने पर हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। हाइपरथायरायडिज्म में आपका थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है इससे हाइपर मेटाबॉलिज्म होता है जिससे हार्ट रेट बढ़ सकता है,इससे टैकीकार्डिया की स्थिति पैदा हो सकती है। इस स्थिति में भी हार्ट का फैलाव हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इस तरह से हार्ट को नुकसान पहुंचता है।

क्या आपको भी बार-बार बर्फ खाने का मन करता है हो सकता है इस बीमारी का संकेत

क्या आपको भी हर वक्त कच्चा बर्फ चबाने का दिल करता है। अगर हां तो आपको फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि यह एक गंभीर डिसऑर्डर की तरफ इशारा करता है।

गर्मियों के मौसम में हर किसी को कुछ ना कुछ ठंडा खाने का मन करता है। ठंडा पानी तो हर कोई पीता है, लेकिन आइसक्रीम मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ लोग तो घर में रखे आइस क्यूब भी खाते हैं। लेकिन अगर आप बार-बार कच्ची बर्फ चबाते हैं तो इसे इग्नोर ना करें। दरअसल आपकी यह आदत किसी बीमारी की तरफ इशारा करती है। आइए जानते हैं बार-बार बर्फ खाने का मन क्यों करता है।

क्या आपको भी बार-बार बर्फ खाने का मन करता है आपको भी बार-बार बर्फ खाने की क्रेविंग होती है तो शायद आप पिका डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। वैसे तो यह बच्चों या गर्भवती महिलाओ में होता है,लेकिन अगर आप में आयरन की कमी हो तो भी आपको इसकी क्रेविंग हो सकती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि एनीमिया से पीड़ित लोगों में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है ऐसे में लोगों को बर्फ खाने की इच्छा बढ़ जाती है। वहीं जो लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं उन्हें भी बर्फ खाने की क्रेविंग होती है। अगर यह क्रेविंग लंबे समय तक बनी हुई है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज करवाना चाहिए।

क्या है इसके नुकसान

- दांतों में दर्द, बर्फ आपके दांत की इनेमल की परत को डैमेज कर सकती है।
- एनीमिया की गंभीर समस्या,इसके कारण हार्ट हेल्थ को नुकसान पहुंचता है।
- पेट में इंफेक्शन और कब्ज की समस्या

छींक क्यों नहीं रोकनी चाहिए

छींक आना नॉर्मल है। लेकिन, अगर आपको बहुत अधिक छींक आती है, तो इसे नजरअंदाज करें। इसके अलावा, अगर आप छींक आते वक्त इसे रोकती है, तो इससे भी सेहत को नुकसान हो सकता है।

हमारा शरीर सेहतमंद रहने के लिए कई नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करता है। पेट साफ होना, गैस बाहर निकलना, डकार आना और छींक आना समेत कई ऐसी चीजें हैं, जिनका हमारी सेहत से गहरा कनेक्शन है। कई बार, नाक के अंदर डस्ट और पाउडर जैसे पार्टिकल्स चले जाते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए, छींक आती है। वहीं, सर्दी-जुकाम होने पर भी छींक आती है। हालांकि, अगर आपको अक्सर बहुत अधिक छींक आती हैं, तो इसके पीछे कुछ हेल्थ कंडीशन्स हो सकती हैं। आमतौर पर छींक आना काफी नॉर्मल होता है। कई लोग, छींक आने पर इसे रोक लेते हैं। लेकिन, सेहत के लिहाज से ऐसा करना गलत है। एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आप छींक रोकती हैं, तो इससे स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इस बारे में डॉक्टर नीतिका कोहली जानकारी दे रही हैं। वह आयुर्वेद में एमडी हैं। उन्हें इस फील्ड मे लगभग 17 सालों का अनुभव है।

छींक रोकने से सेहत को हो सकता है नुकसान

- दरअसल, हमारी नाक में एक म्यूकस नाम की झिल्ली होती है। इसके टिश्यू या सेल्स पर जब कोई डस्ट पार्टिकल आकर चिपकता है, तो इसे बाहर निकालने के लिए छींक आती है।
- आयुर्वेद में छींक को क्षुतु कहा जाता है। इसे अधारणीय वेग कहा जाता है। इसकी गिनती उन वेगों में होती हैं, जिन्हें रोका नहीं जा सकता है और रोकना भी नहीं चाहिए।
- छींक के जरिए, बैक्टीरिया और वायरस नाक से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए, यह फायदेमंद होती है।
- छींक रोकना सेहत के लिहाज से सही नहीं है। इससे गर्दन अकड़ सकती है और साइनस की दिक्कत भी हो सकती है।
- अगर आप छींक आने पर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो इससे फेस की नर्व्स और मसल्स कमजोर हो सकती हैं।
- यह शरीर की सफाई का एक नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए, इसे होल्ड नहीं करना चाहिए।
- एक्सपर्ट के मुताबिक, कई बार सोशल एटिकेट्स या अन्य कई वजहों से लोग छींक को रोक लेते हैं। लेकिन, छींक रोकने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। इससे श्वसन तंत्र पर बुरा असर हो सकता है।
- छींक के जरिए, बाहर निकलने वाली हवा का प्रेशर काफी तेज होता है। इसे रोकने से, आंख, नाक और कान के ब्लड वेसल्स पर असर पड़ सकता है।
- छींक आने पर उसे रोकने की कोशिश न करें। एक्सपर्ट की सलाह पर जरूर ध्यान दें। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है, तो हमें आर्टिकल के ऊपर दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अपने आर्टिकल्स के जरिए आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे।

कलिंग समाचार

संपादकीय

गुरूवार 16 अप्रैल 2026

रश्मि शुक्ला का तबादला विपक्ष की जीत

केन्द्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला का हटाया जाना महाविकास अघाड़ी ;एमवीएद्ध की एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दल कई बार उन पर पक्षपात का आरोप लगा चुके हैं। उन पर मु यतरू विपक्षी नेताओं की फोन टेपिंग कराने के आरोप हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था जिसे अन्य विरोधी दलों का भी समर्थन था। उनका आरोप था कि पुलिस की सर्वोच्च अधिकारी का रुख सत्ताधारी दल के प्रति नरम है जिसके कारण निष्पक्ष चुनाव की उ मीद नहीं की जा सकती। उनकी मांग पर केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने शुक्ला को तत्काल स्थानांतरित करने का महाराष्ट्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि मंगलवार को दोपहर 1 बजे तक वह पुलिस के 3 वरिष्ठतम अधिकारियों के नाम भेजे ताकि नये डीजीपी की नियुक्ति हो। 1988 बैच की आईपीएस रश्मि पर सरकार समर्थक होने का आरोप लगता रहा है। इस साल की जनवरी में सेवानिवृत्त हो चुकी रश्मि शुक्ला का कार्यकाल एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा दो वर्ष के लिये बढ़ाया गया था। माना जाता है कि सेवा बढ़ाये जाने के एवज में वे शिंदे के नेतृत्व में चल रही नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस के पक्ष में कार्य कर रही थींए जिनमें शिवसेना ;शिंदे गुटद्धए भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी ;अजित पवार गुटद्ध शामिल हैं। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं जिसके पहले ज मू.कश्मीर तथा हरियाणा के चुनाव हो चुके हैं। इन राज्यों की समीक्षा बैठक करते हुए केन्द्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों से निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया था ताकि पारदर्शी तरीके से चुनाव स पन्न हो सकें। वैसे चुनाव आयुक्त के इस निर्देश को महज औपचारिकता माना गया था क्योंकि आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड बड़े पैमाने पर भाजपा को मदद करने का रहा है। एक अर्से से चुनाव आयोग को भाजपा की जेब में बैठा हुआ साफ देखा गया है जिसके अनेक उदाहरण हैं। अब यह कहने में कोई गुरेज़ नहीं होना चाहिये कि भाजपाए खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं कुछ प्रमुख नेताओं की सुविधानुसार आयोग सभी तरह के चुनावों का आयोजन करता है। किस राज्य में कितने चरणों में चुनाव होगा. यह भी भाजपा तथा मोदी की इच्छा और पार्टी की सहूलियत के मुताबिक निर्धारित किया जाता है। बात यहीं तक नहीं रुकती। विभिन्न नेताओं के भाषणों तथा प्रचार को लेकर किस पर कार्रवाई करनी है और किसकी ओर से आंखें मूंदनी हैंए यह भी आयोग चेहरा देखकर ही तय करता है। भाजपा के नेताओं को नफरती भाषणों की पूरी छूट होती है। वे अक्सर भाषायी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और असंसदीय व्यवहार अपनाते हैं लेकिन आयोग उसकी उपेक्षा करता है। इसके विपरीत भाजपा विरोधी दलों के नेताओं के भाषणों एवं उद्बोधनों पर कड़ी नज़र रखी जाती है। पिछले कई चुनावों के दौरान देखा गया कि चुनाव आयोग जिस तरह के कथनों पर विरोधी दल के नेताओं को मुस्तैदी से नोटिस जारी करता है या उनके प्रचार पर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों का प्रतिबन्ध लगाता हैए वैसे ही कथन भाजपा के किसी भी नेता की ओर से आते हैं तो वह कानों में रूई डालकर बैठ जाता है। मोदीए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाहए असम के मु यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमाए पूर्व केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत ऐसे कई भाजपायी नेता हैं जिन्होंने हाल के वर्षों की चुनावी रैलियों में जमकर ज़हर उगला था परन्तु किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का नमूना इसी मामलेए यानी डीजीपी वाले में भी दिखा। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के खिलाफ प्रदेश भाजपा इकाई ने शिकायत की थी। उन्हें वहां के मु यमंत्री हेमंत सोरेन का नज़दीकी बतलाया जाता था। इसके साथ ही उनके कथित विवादित इतिहास का भी हवाला दिया गया था। चुनाव का ऐलान होते ही 21 अक्टूबर को गुप्ता को हटाने का निर्देश आयोग ने दियाए लेकिन रश्मि शुक्ला को रहने दिया गया जिनके खिलाफ फोन टेपिंग की शिकायतें हुई हैंय फिर उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था जो उनकी सत्तारुढ़ गठबन्धन से नज़दीकियों को बतलाता है।

आदिवासी बच्चों का अनोखा स्कूल

बाबा मायाराम

यहां आधुनिक रिकार्डिंग स्टूडियों भी हैए जहां आदिवासी संस्कृति पर वीडियो बनाए जाते हैंए इसका भील वॉयस नामक एक यू ट्यूब चैनल भी हैए जिसमें कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। स्कूल की शुरूआत में बिना पाठ्यपुस्तकों के ही पढ़ाई होती थी। भिलाली और हिन्दी में बच्चों को पढ़ना.लिखना सिखाया जाता था। लेकिन जल्द ही पाठ्यक्रम विकसित किया गया। अब तो मध्यप्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा कौशल आधारित शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है। मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के ककराना गांव में ऐसा आवासीय स्कूल हैए जहां न केवल पलायन करने वाले आदिवासी मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं बल्कि हुनर भी सीखते हैं। यहां उनकी पढ़ाई भिलालीए हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में होती है। वे यहां खेती.किसानी से लेकर कढ़ाईए बुनाईए बागवानी और मोबाइल पर वीडियो बनाना सीखते हैं। आज के कॉलम में इस अनोखे स्कूल की कहानी सुनाना चाहूंगाए जिससे यह पता चले कि स्थानीय लोग भी स्कूल बना सकते हैंए चला सकते हैं और उनके बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं।

मैं इस स्कूल को देखने और समझने दो बार जा चुका हूं। स्कूल के अतिथि गृह में ठहरा हूं। इस दौरान शिक्षकोंए छात्रों और ग्रामीणों से मिला हूं। कई गांवों में गया हूं। मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यहां का स्कूल बहुत ही अनुशासितए व्यवस्थित और नियमित है। स्कूल के साथ.साथ प्रकृति से जुड़कर पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। यहां के अधिकांश शिक्षक स्वयं आदिवासी हैंए और इनमें से एक.दो तो इसी स्कूल से पढ़े हैं। पश्चिमी मध्यप्रदेश का अलीराजपुर जिला सबसे कम साक्षरता वाले जिलों में से एक है। यहां के बाशिन्दे भील आदिवासी हैं। यहां की प्रमुख आजीविका खेती है। लेकिन चूंकि असिंचित और पहाड़ी खेती हैए इसलिए अधिकांश लोग पलायन करते है। यहां के अधिकांश लोग राजस्थान और गुजरात में मजदूरी के लिए जाते हैंए इसलिए उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। लेकिन इस आवासीय स्कूल से बच्चों की पढ़ाई हो रही है। इस इलाके में आदिवासियों के हक और स मान के लिए खेडुत मजदूर चेतना संगठन सक्रिय रहा है। शुरूआत में इस संगठन ने अनौपचारिक रूप से आदिवासी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन बाद में इसके कार्यकर्ता कैमत गवले व गांववासियों ने मिलकर ककराना गांव में आवासीय स्कूल की शुरूआत की। यह वर्ष 2000 की बात है। स्कूल का नाम रानी काजल जीवनशाला है। यह स्कूलए मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग में पंजीकृत है और यहां माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है।

स्कूल के प्राचार्य निंगा सोलंकी बताते हैं कि वर्ष 2008 में हमने कल्पांतर शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र समिति गठित कीए जो स्कूल के संचालन के लिए वित्तीय मदद जुटाती है। हाल ही में महिला जगत लिहाज समिति नामक संस्था ने भी संचालन में सहयोग करना शुरू किया हैएजिसकी मदद से नए भवन बने हैं और छात्रावास भी संचालित हो रहा है। स्कूल का सर्व सुविधायुक्त परिसर हैए भवन हैं और 2 एकड़ जमीन हैए जिसमें हरे.भरे पेड़.पौधों के साथ जैविक खेती भी होती है। यह परिसर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां मिट्टी.पानी का संरक्षण होए यह सुनिश्चित किया जा रहा है। मिट्टी का क्षरण न हो और पानी की एक बूंद भी परिसर से बाहर न जाएए इसलिए परिसर में पेड़.पौधों का रोपण किया गया है। यहां सागौनए महुआए शीशमए कटहलए बादामए सीताफलए जामए नीमए नींबूए अंजन जैसे करीब 2000 पौधे रोपे गए हैं। विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन का काम करते हैं। परिसर में सैकड़ों तरह के पक्षियों का बसेरा भी है।

वे आगे बताते हैं कि आदिवासी बच्चों के लिए आवासीय स्कूल की जरूरत हैए क्योंकि उनके परिवार में पढ़ाई.लिखाई का कोई माहौल नहीं है। वे आजाद भारत में पहली पीढ़ी हैंए जो शिक्षित हो रहे हैं। हमने यह महसूस किया कि बच्चों को एक दिन के स्कूल की तुलना में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आवासीय स्कूल का निर्णय लिया गया। दैनिक स्कूलों में कामकाज की समीक्षा से पता चला कि अशिक्षित माता.पिता के बच्चों के प्रभावी शिक्षण के लिए उन्हें नियमित स्कूली घंटों के अलावा भी पढ़ाने की जरूरत है। इन्हें जो शिक्षक पढ़ाते हैंए वे भी उनके बीच के हैं और परिसर में ही रहते हैं।

इस शाला का नाम आदिवासियों की देवी रानी काजल के नाम पर रखा गया है। जिसके बारे में मान्यता है कि यह देवी महामारी व संकट के समय उनकी रक्षा करती है। स्कूल की फीस का ढांचा ऐसा है कि अभिभावक इसे वहन कर सकें।

प्राचार्य सोलंकी बतलाते हैं कि इस स्कूल का उद्देश्य आदिवासी पहचान और संस्कृति का संरक्षण करना भी है। इसमें दूसरी कक्षा तक भिलाली भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इसके बाद हिन्दी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। कुछ भीली किताबों का अंग्रेजी और हिन्दी में भी अनुवाद किया गया है। वे आगे बताते हैं कि यहां पढ़ाई के साथ हाथ के हुनर व कारीगरी सिखाई जाती है। किसानीए लोहारीए बढ़ईगिरीए सिलाई और बागवानी इसमें प्रमुख हैं। पिछले वर्ष मध्यप्रदेश शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित पांचवी और आठवीं कक्षा की परीक्षाओं में इस विद्यालय के विद्यार्थी जिले में अव्वल आए थे। कुछ अधिकारी और सरकारी नौकरियों में गए हैं। स्कूल के एक शिक्षक हैंए जो पहले इसी स्कूल के विद्यार्थी रह चुके हैं। पहली बार नर्मदा किनारे गांवों की लड़कियां पढ़ रही हैंए और उनमें से एक शिक्षिका भी बन गई हैं।

स्कूल के प्राचार्य निंगा सोलंकी बताते हैं कि वर्ष 2008 में हमने कल्पांतर शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र समिति गठित कीए जो स्कूल के संचालन के लिए वित्तीय मदद जुटाती है। हाल ही में महिला जगत लिहाज समिति नामक संस्था ने भी संचालन में सहयोग करना शुरू किया हैएजिसकी मदद से नए भवन बने हैं और छात्रावास भी संचालित हो रहा है। स्कूल का सर्व सुविधायुक्त परिसर हैए भवन हैं और 2 एकड़ जमीन हैए जिसमें हरे.भरे पेड़.पौधों के साथ जैविक खेती भी होती है। यह परिसर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां मिट्टी.पानी का संरक्षण होए यह सुनिश्चित किया जा रहा है। मिट्टी का क्षरण न हो और पानी की एक बूंद भी परिसर से बाहर न जाएए इसलिए परिसर में पेड़.पौधों का रोपण किया गया है।

इसके अलावाए यहां आधुनिक रिकार्डिंग स्टूडियों भी हैए जहां आदिवासी संस्कृति पर वीडियो बनाए जाते हैंए इसका भील वॉयस नामक एक यू ट्यूब चैनल भी हैए जिसमें कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

स्कूल की शुरूआत में बिना पाठ्यपुस्तकों के ही पढ़ाई होती थी। भिलाली और हिन्दी में बच्चों को पढ़ना.लिखना सिखाया जाता था। लेकिन जल्द ही पाठ्यक्रम विकसित किया गया। अब तो मध्यप्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा कौशल आधारित शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है।

हर साल गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्राचार्य निंगा सोलंकी और शिक्षिका रायटी बाई ने नई शिक्षण पद्धति अपनाई है। वे पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षणिक वीडियो व आडियो बनाते हैंए जिन्हें बाद में बच्चों के माता.पिता के मोबाइल पर साझा किया जाता है। इससे बच्चे परिसर के बाहर घर में भी उनकी पढ़ाई जारी रखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए फोन कॉल और संदेशों का आदान.प्रदान भी किया जाता है।प्राचार्य सोलंकी बतलाते हैं कि आदिवासियों की संस्कृतिए बोलियां और जीवनशैली आधुनिक प्रभावों के कारण तेजी से बदल रही है। उनकी पारंपरिक जीवनशैली का अनूठापन लुप्त हो रहा हैए इसलिए हमने भीली में यह कार्यक्रम शुरू किया हैए जिससे उसका संरक्षण किया जा सके।

इसके लिए अमेरिका में प्रवासीय भारतीय प्रोफेसर उत्तरन दत्ता ने सहयोग दिया है और उनके मार्गदर्शन में 15.20 बच्चों को मोबाइल वीडियोग्राफी और वीडियो संपादन का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके माध्यम से लोकगीतए कहानियां और पारंपरिक उपचार विधियों और जंगलों के खान.पान व महत्व पर आधारित कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

कुल मिलाकरए यह आदिवासी मजदूर बच्चों का आवासीय स्कूल हैए जिसमें न केवल पढ़ाई करते हैंए बल्कि गतिविधि आधारित शिक्षा भी हासिल करते हैं। प्रकृति अवलोकनए श्रम आधारित उत्पादन पद्धति से भी सीखते हैं। उनकी भीली.भिलाली भाषा में मौलिक अभिव्यक्ति भी करते हैं। इसके लिए उनका यू ट्यूब चैनल भी है। इस स्कूल के मूल्यों में एक आदिवासी पहचानएसंस्कृति व अच्छी परंपराओं का संरक्षण करना भी है। इस स्कू ल की खास बात यह भी है कि स्कूली शिक्षक उनके बीच रहते हैं। जिज्ञासाए सवाल व समस्याओं के हल के लिए सहज ही उपलब्ध हैं। वे एक परिवार की तरह रहते हैं। बच्चों को तोतारटंत किताबी ज्ञान नहींए बल्कि श्रम के मूल्य साथ समझ विकसित करने की कोशिश की जाती है। इस स्कूल ने श्रम के मूल्य का बोध भी कराया हैए जिसका पूरी शिक्षा व्यवस्था में लोप हो गया है। यह पूरी पहल सराहनीय होने के साथ अनुकरणीय भी है।

डॉक्टरों की बढ़ती आत्महत्याएं–चिकित्सकों को चिकित्सा की जरूरत

अमरपाल सिंह वर्मा

सरकारए मेडिकल संस्थानोंए इंडियन मेडिकल एसोसिएशनश् और समाज को मिलकर ऐसे उपाय करने होंगेए जिससे डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के लिए काम और जीवन के बीच संतुलन कायम करना आसान हो। यह भी आवश्यक है कि समाज की ओर से डॉक्टरों पर अनावश्यक अपेक्षाओं का बोझ न डाला जाए। डॉक्टर भी इंसान हैंए उनकी भावनाओं और सीमाओं का स मान किया जाना चाहिए।

लोगों की सेवा एवं उनका इलाज करने के लिए जुटे रहने वाले डॉक्टर गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नलश् में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट चिंतित कर देने वाली है। इस रिपोर्ट में डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति पर गहरी चिंता जताई गई है। इसमें यह तथ्य सामने आया है कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों और डॉक्टरों में आत्महत्या का खतरा आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। महिला डॉक्टरों पर इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तनाव की वजह से आत्महत्या का सबसे अधिक खतरा महिला डॉक्टरों को है। इस शोध के अनुसार महिला डॉक्टरों में आत्महत्या का खतरा आम लोगों की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। भारत में किए गए अध्ययनों से भी यह स्पष्ट हुआ है कि 40 प्रतिशत महिला डॉक्टर अत्यधिक तनाव में काम करती हैं। इस तनाव का सीधा संबंध मेंटल डिस्ऑर्डर और आत्महत्या के विचारों से है। इंडियन जर्नल ऑफसाइकियाट्रीश् में प्रकाशित एक शोध से भारत के डॉक्टरों के लिहाज से भी चिंताजनक तस्वीर उभरती है। इस जर्नल के आंकड़ों के अनुसारए पिछले एक दशक में भारत में 358 डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने आत्महत्या की है जिनमें से 70 प्रतिशत की उम्र मात्र 30 से 40 वर्ष के बीच थी। यह आंकड़ा केवल एक नंबर नहीं है बल्कि यह समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। जब देश के युवा और प्रतिभाशाली डॉक्टर तनाव और मानसिक दबाव के कारण अपनी जान लेने पर मजबूर हो रहे हैं तो यकीनन यह हमारे हेल्थ केयर सिस्टम और समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।

भारत के अध्ययनों से पता चलता है कि 40 प्रतिशत महिला डॉक्टरों को अत्यधिक तनाव की हालातों में काम करना पड़ रहा है। बढ़ता मानसिक असंतुलन और आत्महत्या के विचार इसके कारण हैं। डॉक्टर एमबीबीएस के बाद विशेषज्ञ बनने के लिए पीजी की तैयारी में जुट जाते हैं। एक तरफकाम का दबाव होता हैए दूसरी ओर पढ़ाई की चिंता सताती है। इससे उपजे तनाव में संतुलन रखना बहुत कठिन होता है। शायद इसी का परिणाम है कि पिछले पांच सालों में 1270 मेडिकल छात्रों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इनमें 153 एमबीबीएस तथा 1117 पीजी में एडमिशन लेने वाले छात्र थेए जो एमबीबीएस के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर बनने की चाह लिए हुए थे।हमारे देश में आत्महत्या करने वाली महिला डॉक्टरों में सर्वाधिक 22ण्4 प्रतिशत श्एनेस्थीसिया विभागश् ;निश्चेतनाद्ध की एवं 16 प्रतिशत श्स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागश् की थीं। इन विभागों के डॉक्टरों के पास ही सर्वाधिक श्हाई.रिस्कश् वाले मरीज आते हैंए इसलिए उन पर काम का दबाव एवं तनाव ज्यादा होता है।

डॉक्टरों की भारी कमी वाले हमारे देश में बन रहे ये हालात बहुत बुरे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी की वजह से लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर भागना पड़ रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि देश में डॉक्टर.जनसं या अनुपात श्विश्व स्वास्थ्य संगठनश् ;डब्ल्यूएचओद्ध की ओर से निर्धारित मानदंडों से बेहतर हैए मगर स्वास्थ्य मंत्रालय के पिछले साल के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में श्सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रोंश् ;सीएचसीद्ध में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। मंत्रालय द्वारा जारी भारत की श्स्वास्थ्य गतिशीलता ;बुनियादी ढांचा और मानव संसाधनद्ध 2022.23 रिपोर्टश् के निष्कर्षों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्सीएचसीश् में जरूरी 21 हजार 964 सर्जनए प्रसूतिध्स्त्री रोग विशेषज्ञए फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञों के मुकाबले भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 17 हजार 551 विशेषज्ञों की कमी है।सीनियर डॉक्टरों की मानें तो मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों पर अत्यधिक दबाव उनके लंबे और कठोर प्रशिक्षणए भारी कार्यभारए सामाजिक अपेक्षाओं और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी से उत्पन्न होता है। महिला डॉक्टरों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ.साथ पारिवारिक जि मेदारियों का भी संतुलन बनाना पड़ता हैए जिससे उनकी स्थिति और जटिल हो जाती है। अस्पतालों में तोड़फोड़ए डॉक्टरों से मारपीट और अभद्र व्यवहार जैसी घटनाएं भी इस स्थिति के लिए कम जि मेदार नहीं हैं।

वर्ष 2022 में राजस्थान के लालसोट में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत होने पर धरने.प्रदर्शन और पुलिस द्वारा अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से परेशान होकर सुसाइड कर लेने वाली युवा चिकित्सक डॉण् अर्चना शर्मा की मौत आज भी झकझोरती है। डॉण् अर्चना ने सुसाइड नोट में लिखा था कि श्श्मैंने कोई गलती नहीं की हैए किसी को नहीं मारा। प्रसवोत्तर रक्तस्राव ;पीपीएचद्ध एक कॉम्प्लिकेशन हैए इसके लिए डॉक्टरों को प्रताड़ित करना बंद करो।श्श् हाल में भरतपुर के रेडियोलॉजिस्ट डॉण् राजकुमार चौधरी ने आगरा में जाकर सुसाइड कर ली है। पूरे देश में इस तरह के मामले आते रहते हैं।

यह समस्या बहुत बड़ी है जिसका त्वरित समाधान होना चाहिएए लेकिन यह तभी हो सकता हैए जब समस्या की जड़ों तक पहुंचकर असलियत की थाह ली जाए। यह जरूरी है कि महिला डॉक्टरों के दृष्टिगत श्हेल्थ केयर सिस्टमश् में लिंग संवेदनशील रणनीतियां प्रभावी ढंग से लागू की जाएं। कामकाजी माहौल को महिला डॉक्टरों के लिए अधिक अनुकूल बनाना होगा। इसके साथ हीए डॉक्टरों और छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।

सरकारए मेडिकल संस्थानोंए इंडियन मेडिकल एसोसिएशनश् और समाज को मिलकर ऐसे उपाय करने होंगेए जिससे डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के लिए काम और जीवन के बीच संतुलन कायम करना आसान हो। यह भी आवश्यक है कि समाज की ओर से डॉक्टरों पर अनावश्यक अपेक्षाओं का बोझ न डाला जाए। डॉक्टर भी इंसान हैंए उनकी भावनाओं और सीमाओं का स मान किया जाना चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर समाज के लिए जुटे रहते हैंए उसी प्रकार समाज के प्रत्येक वर्ग को भी डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य एवं सुकून को बनाए रखने के लिए योगदान देना चाहिए।

विविध समाचार

आदिवासी परिवारों को शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य और विकास के मिल रहे नए अवसर : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित 'आदि कर्मयोगी अभियान', 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' तथा 'प्रधानमंत्री जनमन अभियान' को जनजातीय समाज के उत्थान हेतु महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये सभी योजनाएँ देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों को शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य और विकास के नए अवसर प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु आज अज़्बिकापुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम को सज़्बोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, और इसकी झलक बस्तर की 'मुरिया दरबार' जैसी जनजातीय परंपराओं में भी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि छज़ीसगढ़, झारखंड और ओडिशा की जनजातीय विरासत अत्यंत समृद्ध और आपस में जुड़ी हुई है।

उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति भवन में 'जनजातीय दर्पण' संग्रहालय की स्थापना की गई है, तथा वहां आदिवासी कला और संस्कृति को विशेष स्थान दिया गया है। राष्ट्रपति ने अपने सज़्बोधन में छज़ीसगढ़ में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाने, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाने और शासकीय योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छज़ीसगढ़ सरकार और मुज़्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आयोजित 'आदि कर्मयोगी' राष्ट्रीय सज़्मेलन में छज़ीसगढ़ के आदिवासी विकास विभाग को उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस उपलज़्धि के लिए मुज़्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा उनकी पूरी टीम को बधाई दी। छज़ीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस अपनी पहचान, सांस्कृतिक विरासत और उन वीर पूर्वजों को स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने जनजातीय इतिहास

को गौरवशाली अध्यायों से भर दिया। समारोह में उपस्थित देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का सज़्मान करते हुए राज्यपाल ने कहा कि एक साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुँचने की उनकी प्रेरक यात्रा पूरे भारत के लिए उदाहरण है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने उनके व्यक्तित्व और संघर्ष के कई प्रेरक प्रसंगों को याद किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने नशाखोरी, अन्याय और अंधविश्वास के खिलाफसाहसिक अभियान चलाया। उनके नेतृत्व में हुआ 'उलगुलान' ब्रिटिश शासन को चुनौती देने वाला ऐतिहासिक आंदोलन था, जिसने जनजातीय स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह, राजा गेंद सिंह, कंगला मांझी, वीर सीताराम कंवर और गुंडाधुर जैसे महानायकों ने अपने बलिदान और संघर्ष से स्वतंत्रता आंदोलन और जनजातीय गौरव को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। उनका योगदान प्रदेश की स्मृतियों में सदा अमर रहेगा।मुज़्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह छज़ीसगढ़ का सौभाग्य है कि राष्ट्रपति जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस समारोह में शामिल होकर प्रदेश की गरिमा बढ़ाई है। कुछ दिन पूर्व नज़्सल पीड़ित परिवारों से राष्ट्रपति की भेंट का उल्लेख करते हुए मुज़्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रत्येक पीड़ित से आत्मीयता से हाल-चाल जानकर अपनी ममतामयी छवि प्रस्तुत की।

मुज़्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छज़ीसगढ़ का इतिहास अत्यंत समृद्ध है और यहाँ के आदिवासी समाज ने देश की स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान दिया है। हाल ही में 1 नवज़्बर को आयोजित रजत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भी उपस्थित थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई से जुड़े आदिवासी महापुरुषों पर आधारित ज़्यूज़ियम का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि जनजातीय विद्रोह के नायकों की स्मृति को सहेजने हेतु शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह-संग्रहालय का निर्माण किया गया है, जिसे राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा जनता को समर्पित किया गया। यह देश का पहला जनजातीय संग्रहालय है, जिसमें डिजिटल माध्यम से जनजातीय गौरवगाथा को देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के करकमलों से आज जनजातीय विद्रोह के नायकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों का सज़्मान होना सभी के लिए गौरव का विषय है। साथ ही जनजाति एवं उपजनजाति प्रमुखों को भी सज़्मानित किया गया, जो अपने ज्ञान और अनुभव से समाज को निरंतर जागरूक कर रहे हैं।मुज़्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 53 विकासखंडों की 2,365 बसाहटों में तीव्र गति से विकास कार्य हो रहे हैं, इसी इच्छाशक्ति से नज़्सलवाद अब अंतिम चरण में है, और मार्च 2026 तक इसके समूल नष्ट होने के लक्ष्य की ओर प्रदेश तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि छज़ीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के चलते नज़्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास का उजाला पहुँचा है। आकर्षक पुनर्वास नीति के कारण कई भटके हुए लोग मुज़्यधारा से जुड़कर सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और सरकार की विभिन्न योजनाओं से जनजातीय समाज निरंतर लाभान्वित हो रहा है।केंद्रीय राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उईके ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल झारखंड या जनजाति समाज के नायक ही नहीं थे बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए स्वाभिमान, सज़्मान, गौरव, गरिमा और सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण जनहित और स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए समर्पित किया। उन्होंने अपने समाज को संगठित किया, उन्हें आत्मसज़्मान और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु भी थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसका जन्म किसी भी समाज में हुआ हो अगर उसके भीतर सच्ची लगन और आत्मबोध है तो वह इतिहास बदल सकता है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत काल में देश भर के जनजाति समाज के महानायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, महापुरुषों को चिन्हित करके उन्हें इतिहास में उचित स्थान दिया जा रहा है।

जनजाति समाज के महापुरुषों के जन्म स्थलों पर स्मारक बनाए जा रहे हैं। जनजाति समाज के लोग के पूजा स्थलों को चयनित कर उनका पुनरुत्थान किया जा रहा है।

चंद्रखुरी में प्रभु श्री राम की गरिमा अनुरूप भव्य मूर्ति स्थापना के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल की निर्णायक पहल

रायपुर। छज़ीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार पुन: धर्मनगरी चंद्रखुरी से जुड़े करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए मुज़्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि में मर्यादा पुरुषोज़म भगवान श्री राम की गरिमा एवं पारंपरिक स्वरूपानुकूल भव्य मूर्ति की स्थापना की मांग की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में लगाई गई मूर्ति का स्वरूप प्रभु श्री राम की पारंपरिक छवि से मेल नहीं खाता था, जिसके कारण व्यापक जन-विरोध उत्पन्न हुआ। श्री अग्रवाल ने न केवल इस विषय को सार्वजनिक मंचों पर बार-बार उठाया, बल्कि विधानसभा में भी दृढ़ता के साथ आवाज बुलंद करते हुए प्रभु श्री राम की गरिमा संगत नई मूर्ति स्थापना की मांग को मजबूती से रखा था। सांसद ने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद भी यह मांग लगातार उठती रही, किंतु लगभग दो वर्षों के बाद भी मूर्ति परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से जनता में निराशा व्याप्त है। उनके संज्ञान में आया कि छज़ीसगढ़ के लिए निर्मित नई मूर्ति ग्वालियर में तैयार होने के बावजूद विभागीय उदासीनता के कारण उसे किसी अन्य राज्य में स्थापित किए जाने की स्थिति बन रही है—जो अत्यंत चिंतनीय है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुज़्यमंत्री से आग्रह किया है कि अगले तीन महीनों के भीतर चंद्रखुरी में प्रभु श्री राम की पारंपरिक स्वरूपानुकूल भव्य मूर्ति की स्थापना सुनिश्चित की जाए तथा माँ कौशल्या की जन्मभूमि के समग्र विकास हेतु एक विस्तृत मास्टर प्लान बनाकर प्राथमिकता से कार्य आरंभ किया जाए।

सांसद बृजमोहन के प्रयासों से राजधानी के पर्यावरण सुधार के लिए अब तक का सबसे बड़ा पैकेज

रायपुर/नई दिल्ली। छज़ीसगढ़ की जनता को स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण देने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम दर्ज हुआ है। लोकसभा में 19 अगस्त को नियम 377 के तहत छज़ीसगढ़ के पर्यावरणीय संकट को मुखरता से उठाने वाले रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर केंद्र सरकार ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए रायपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई के लिए 301.69 करोड़ रुपये का स्वच्छ वायु अनुदान स्वीकृत किया है। इनमें से अकेले रायपुर शहर को 151.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं—जो राजधानी के पर्यावरण सुधार के लिए अब तक का सबसे बड़ा विज़ीय पैकेज है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव ने 18 अज़्टूबर को सांसद श्री अग्रवाल को पत्र लिखकर सूचित किया कि छज़ीसगढ़ के तीन बड़े शहर वायु गुणवज़ा मानकों को पूरा न करने के चलते राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं। कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन और प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन के बाद इन शहरों को बड़ी राशि प्रदान की गई है।

कोरबा शहर को मंत्रालय की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत सहायता दी जाती है, जबकि रायपुर, दुर्ग और भिलाई जैसे 10 लाख से अधिक जनसंज़्या वाले शहरों को 15वें वित्त आयोग के वायु गुणवज़ा अनुदान से वित्त पोषित किया जाता है। यह सिर्फअनुदान नहीं—छज़ीसगढ़ की सेहत का सुरक्षा कवच है: सांसद बृजमोहन अग्रवाल स्वच्छ वायु अनुदान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त करते हुए सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि छज़ीसगढ़ की करोड़ों जनता की सेहत और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। मैंने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया ज़्योंकि स्वच्छ हवा हर नागरिक का अधिकार है।

केंद्र सरकार ने जिस तत्परता और गंभीरता से हमारी बात मानी, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी प्रत्येक रुपये का उपयोग पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-हित सर्वोपरि रखते हुए किया जाएगा।

हमारा लक्ष्य स्पष्ट है स्वस्थ छज़ीसगढ़, सुरक्षित छज़ीसगढ़। औद्योगिक क्षेत्रों की प्रदूषण स्थिति पर भी निर्णायक कदम राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने रायपुर क्षेत्र में औद्योगिक स्रोतों से होने वाले प्रदूषण का विस्तृत अध्ययन किया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिलतरा और रायपुर औद्योगिक क्षेत्र को क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया घोषित किया है। इसी के मद्देनज़र छज़ीसगढ़ पर्यावरण मंडल को उरला, सिलतरा, कोरबा और भिलाई औद्योगिक ज़लस्टरों में पर्यावरणीय गुणवज़ा बहाली की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 12 सितंबर 2025 को ष्टक्कष्टक्क ने गंभीर प्रदूषित क्षेत्रों की कार्ययोजनाओं की समीक्षा भी की है।

जनता की आवाज़ संसद तक पहुँची—अब धरातल पर दिखेगा बड़ा बदलाव सांसद बृजमोहन अग्रवाल की दूरदर्शी सोच, मजबूत पैरवी और निरंतर प्रयासों के चलते आज छज़ीसगढ़ के तीन प्रमुख शहरों को वह आर्थिक शक्ति मिली है, जिससे आने वाले वर्षों में वायु गुणवज़ा में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।

राजनीति को गंगाजल से धोने वाले नेता : नरेंद्र मोदी

नरेंद्र मोदी के बारे में कोई कुछ भी कहे लेकिन एक बात तो सर्वमान्य होगी कि उन्होंने देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है, सीधे तौर पर कहें तो मोदीजी ने राजनीति में भूचाल ला दिया है। मोदी जी से पहले भारत की राजनीति में कोई रोमांच नहीं था, यहां तक कि लोग न्यूज भी ठीक से नहीं देखते थे लेकिन आज लोग टीवी के सामने ही बैठे रहते हैं न्यूज देखते हैं डिबेट सुनते हैं और तो और बड़ी संख्या में पोलिटिकल डिबेट में शामिल होते हैं। यह मोदी फैक्टर ही है कि जो मध्यम वर्ग खुद को राजनीति से दूर रखता था, सिर्फ करिअर ओरिएंटेड ही था वह भी आज राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगा है। लगे हाथ इसी में महिलाओं की भूमिका की समीक्षा भी कर ली जाये। आज मोदी जी ने सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन यही किया है कि देश की महिलाएँ अब राजनीति में बहुत बड़ी मात्रा में सक्रिय हुई हैं, जो गृहणियां पहले राजनीति

को अछूत मानती थीं वे आज चुनावी राजनीति कर रही हैं। आजादी के आंदोलन में जो काम महात्मा गांधी ने किया था वही काम आज मोदीजी ने किया है। आज देश में हर वर्ग की महिलाएँ यदि राजनीति में सक्रिय हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण हैं नरेंद्र मोदी। छोटे छोटे गाँव की महिलाएं भी आज मोदी भक्त हैं, वो किसी नेता को जानती हैं तो सिर्फ मोदी जी को। उनको भले ही अपने गाँव के सरपंच नाम पता नहीं होगा लेकिन मोदी का नाम ऐसे लेती हैं जैसे वो इनके घर के सदस्य हों। मुझे अपने कार्यक्रमों के लिए पूरे देश में जाने का सौभाग्य मिलता है, महानगर से लेकर पंचायत तक मैं जाता हूँ तब यह परिवर्तन और मोदी प्रेम मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। आज हालत यह है कि महिलाएँ मोदी के खिलाफ सुनना भी नहीं चाहती, पहले इतना सपोर्ट महिलाएँ सिर्फ गांधी जी का करती थीं। असल में मोदीजी से पहले राजनीति खघसकर चुनावी राजनीति सिर्फ डंडों और गुंडों से चलती थी और उत्तर भारत में तो चुनाव सिर्फ नाम के लिए होते थे,असली काम तो दादागिरी से ही होता था। महिलाओं में डर का इतना माहौल था कि महिलाएं चुनाव लड़ना तो दूर, वोट डालने भी नहीं जाती थीं लेकिन मोदीजी उनको न केवल बूथ तक लाने में सफल हुए हैं बल्कि वोट किसको देना हैं और क्यों देना है यह समझाने में भी सफल हुए हैं। इसीलिए इन दिनों महिलाओं का वोटिंग पर्सेंटेज बहुत तेजी से बढ़ा है और खास बात यह है महिलाओं का वोट ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ मोदीजी को जाता है फिर चाहे वो किसी भी वर्ग या समाज की हो। कई घरों का हाल तो यह है कि पुरुष विपक्षी पार्टी को वोट देते हैं लेकिन उनके घर की महिलाओं का वोट फिक्स है मोदी को। महिलाओं को यह खुद का निर्णय लेने की ताकत भी मोदीजी ने ही दी है। पहले महिलाएं पिता,भाई,पति, जेठ या ससुर के कहने से वोट डालती थीं। लेकिन अब वो मोदी को ही वोट देती हैं और मीडिया में आकर भी साफ साफ कहती हैं हम तो मोदी को जिताएंगे और बाजू में खड़े उनके पति के पास चुपचाप सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

आरएसपी की विशेषज्ञ चिकित्सा टीम के अनुकरणीय बहु-विषयक प्रयासों से कोमाग्रस्त रोगी पुनर्जीवित

राउरकेला १५/०४ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के इस्पात जनरल अस्पताल (आईजीएच) के समर्पित चिकित्सकों की टीम ने समन्वित बहु-विषयक चिकित्सा सेवा के माध्यम से एक कोमाग्रस्त रोगी को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करके एक बार फिर अपनी असाधारण चिकित्सा विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है।एक 71 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर (पुरुष), को 48 घंटे से अधिक समय तक कोई प्रतिक्रिया न देने के बाद गंभीर हालत में आईजीएच के आपातकालीन कक्ष में लाया गया था। रोगी को न्यूरोसर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया और तुरंत आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया। मस्तिष्क के सीटी स्कैन से द्विपक्षीय फ्रंटो-टेम्पोरो-पैरिएटल सबएक्यूट एसडीएच का पता चला।

इसके अलावा, वह सेप्टीसीमिया के साथ दोनों निचले अंगों में गंभीर सेल्युलाइटिस से पीड़ित थे, भर्ती होने से पहले उनका उचित प्रबंधन नहीं किया गया था, और उन्हें गंभीर रूप से उपेक्षित अवस्था में भर्ती कराया गया था। भर्ती होने पर, रोगी को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, उन्हें सक्रिय रूप से पुनर्जीवित किया गया और सर्जरी के लिए ले जाया गया।

न्यूरोसर्जरी के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. मनोज कुमार देव ने ऑपरेशन थिएटर में सिस्टर अर्चना की सहायता से एक बर होल प्रक्रिया की। दोनों निचले अंगों के सेल्युलाइटिस का प्रबंधन वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. गिरिजा शंकर साहू और प्लास्टिक सर्जरी की वरिष्ठ सलाहकार डॉ. रूबी सिंह ने प्रभावी ढंग से किया।रोगी लगभग एक महीने तक आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहा, जहाँ उसे एनेस्थीसिया एवं आईसीयू की अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजुक्ता पाणिग्रही के मार्गदर्शन में विशेष देखभाल मिली। वेंटिलेटर से सफलतापूर्वक मुक्त होने के बाद, उसे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। सिस्टर शाइनी, सिस्टर गुलाब, सिस्टर गौरी, सिस्टर सस्मिता, सिस्टर मनीषा और अन्य की निरंतर चिकित्सा देखरेख और समर्पित नर्सिंग देखभाल में, रोगी में उल्लेखनीय सुधार हुआ, उसकी इंद्रियाँ पुनः जागृत हुईं, वह मुँह से भोजन ग्रहण करने लगा, और अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने और उनसे बातचीत करने लगा। लगभग 60 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद, रोगी लगातार स्वस्थ हो रहा है और अपनी जीवंत शायरियों से कर्मचारियों और आगंतुकों, दोनों को प्रसन्न कर रहा है।

ऊर्जा प्रबंधन विभाग में तत्काल मान्यता योजना के अंतर्गत ठेका श्रमिकों को किया गया पुरस्कृत

राउरकेला १५/०४ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र के ऊर्जा प्रबंधन विभाग में तत्काल मान्यता योजना के अंतर्गत एक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक (ईएमडी),श्री पी. एस. कन्नन ने समारोह की अध्यक्षता की और विभिन्न एजेंसियों के 10 ठेका श्रमिकों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक (ईएमडी), श्री ए. एस. खाखा, महाप्रबंधक (ईएमडी), श्री के. के. बारला, वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन-सीएलसी), सुश्री संगीता एम. सिंदूर, तथा ईएमडी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी, विभिन्न एजेंसियों के संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित थे।

श्री कन्नन ने सभी पुरस्कार विजेताओं की उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशंसा की और अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में गुणवत्ता, लागत और सुरक्षा के महत्व पर बल दिया तथा उपस्थित सभी लोगों को सक्रिय रूप से कार्य करने और लक्ष्यों से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उल्लेखनीय रूप से, संविदा कर्मचारियों को सीपीपी-1 के निकट स्थापना के बाद पहली बार 2600 मिमी व्यास की एमबी पाइपलाइन को बदलने और एमआरडी चौक के निकट 200 मिमी ऑक्सीजन लाइन के स्थानांतरण के लिए पुरस्कृत किया गया।वरिष्ठ प्रबंधक, (ईएमडी), श्री हिमांशु मिश्रा ने इस कार्यक्रम का समन्वय किया।

हाथी दांत की तस्करी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार, 4 दांत बरामद

बड़बिल १५/०४ (संवाददाता): वन्यजीव अपराध के विरुद्ध लड़ाई में एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए ज्योंझर वन प्रभाग ने हाथी दांतों के अवैध कब्जे और व्यापार में संलिप्त पांच व्यक्तियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है।शुक्रवार को ज्योंझर वन प्रभाग कार्यालय में डीएफओ धनराज एचडी ने बताया कि उक्त अभियान की योजना और क्रियान्वयन ज्योंझर वन प्रभाग और सिमलीपाल वन्यजीव खुफिया नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।प्रभागीय वन अधिकारी ज्योंझर के मार्गदर्शन में संचालित अभियान के तहत विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर गुरुवार को एक विशेष कार्रवाई दल का गठन किया गया। जिसमें एसीएफ सुदीप्त पंडा, रेंज अधिकारी नायककांत साहू, भुइयां जुआंगा पिढ़ा रेंज, वनपाल कालिंदी, सी. सामल, ज्योतिर्मयी पटनायक, सरोज कुमार पात्रा, वन रक्षक सुब्रत पात्रा, मित्रभानु नायक, और मिलिरानी दाश शामिल थे और सूचना मिली कि भुइयां जुआंगा पिराह रेंज के सुआकाटी सेक्शन के बांसपाल बीट के अंतर्गत बालीबेड़ा गांव में हाथी दांतों का सौदा होने वाला था।सूचना मिलते ही टीम ने एसीएफ द्वारा जारी तलाशी वारंट प्राप्त किया और शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे टीम ने बालीबेड़ा गांव में गंगाधर पात्रा के परिसर में छापा मारा और पांच व्यक्तियों के पास से लगभग पांच किलोग्राम वजन के चार हाथी दांत पाए गए।टीम द्वारा हाथियों के दांतों को जब्त करने के बाद 41 वर्षीय गंगाधर पात्रा ग्राम बालीबेड़ा, थाना नायकोट, जिला ज्योंझर निवासी, 25 वर्षीय नारद मुंडा, गांव जंभिरिपोसी, थाना नायकोट, जिला ज्योंझर निवासी, 49 वर्षीय केदारनाथ पात्रा ग्राम भलियाडीहा थाना ररुआं, जिला मयूरभंज निवासी, 45 वर्षीय कृष्ण चंद्र मुंडा, ग्राम जोड़ापोखरी, थाना चंपुआ, जिला ज्योंझर निवासी, 30 वर्षीय घासीराम मुंडा ग्राम बारदापाल, थाना सदर (रायसुआं), जिला ज्योंझर निवासी को मौके से गिरफ्तार किया गया। डीएफओ धनराज एच डी ने बताया कि हाथी के दांतों के अतिरिक्त अपराध में प्रयुक्त चार मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं।

ओडिशा सीमा पर घुसपैठ को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी चेतावनी दी सुरेश पुजारी ने

भुवनेश्वर १५/०४ (संवाददाता): राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने ओडिशा सीमा पर घुसपैठ को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल एक असभ्य सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ओडिशा पश्चिम बंगाल को भी पाठ पढ़ाएगा और रास्ता दिखाएगा। राजस्व मंत्री पुजारी बालेश्वर जिले के उदयपुर एवं सहाबाजीपुर में घुसपैठ पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओडिशा की सीमाएंए छत्तीसगढ़ए झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ हैं। मैंने जिले का दौरा किया है और अधिकारियों के साथ चर्चा की है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ ज्यादा समस्याएं नहीं हैंए लेकिन हैरानी की बात यह है कि ओडिशा बनने के बाद से आज तक बालेश्वर में सीमा चिह्नित नहीं हो पाई है। राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग पश्चिम बंगाल सरकार के साथ संपर्क में है। शांतिपूर्ण माहौल में सीमाओं का पता लगाया जाएगा। इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के राजस्व अधिकारी के साथ.साथ ओडिशा के राजस्व अधिकारी क्षेत्र का दौरा करके सीमा की पहचान करेंगे। यह सरकार बिना किसी विवाद के सीमाओं के सीमांकन की समस्या का समाधान करेगी।

पश्चिम बंगाल सरकार एक असभ्य सरकार है। पश्चिमी बंगाल देश में समस्याएं पैदा कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता कानून लागू नहीं किया हैए वह वर्षों से आलू को ओडिशा पहुंचने से रोककर समस्याएं पैदा कर रहे हैं।बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की। यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। पश्चिम बंगाल सरकार विवाद पैदा करने के लिए काम करती है। पश्चिम बंगाल झगड़े पैदा करने का काम कर रहा है। उन्हें पढ़ाई करने की जरूरत है। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि ओडिशा सरकार उन्हें रास्ता सिखाएगी। जबरदस्ती की परवाह कौन करता हैघ् अगर पश्चिम बंगाल सरकार खूंटा लगाएंगेए तो ओडिशा के लोग उन्हें उखाड़ देंगे।

भुवनेश्वर सीबीआई को 7 साल बाद मिली बड़ी सफलता

चिटफंड घोटाले के आरोपी को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार

भुवनेश्वर १५/०४ (संवाददाता):ओडिशा में लंबे समय से चल रही चिटफंड घोटाले की जांच के तहत एक बड़ी सफलता में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शिवकुमार गंगाधरण को गिरफ्तार किया है, जो कई वर्षों से फरार था।उसे तमिलनाडु के कूनूर से भुवनेश्वर सीबीआई कार्यालय की एक टीम ने गिरफ्तार किया। शिवकुमार गंगाधरण, राइटमैक्स टेक्नोट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड का पूर्व निदेशक था और वह 2018 से गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था।सीबाअई अधिकारियों के अनुसार, वह बार-बार अपना ठिकाना बदलता रहा, ताकि जांच एजेंसियों को गुमराह कर सके और उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया। विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने के बाद, सीबीआई टीम ने तमिलनाडु में एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया और अंततः उसे कूनूर में पकड़ लिया, जहां वह एक नकली नाम से रह रहा था। गंगाधरण के खिलाफ चिटफंड धोखाधड़ी का मामला 2014 से जुड़ा है, जब कई निवेशकों ने उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराई थीं। आरोप है कि उसकी कंपनी ने लोगों से भारी रकम यह कहकर ली थी कि उन्हें ऊंचा मुनाफा मिलेगा।इसके बाद साल 2019 में कई बार समन जारी होने के बावजूद जब वह अदालत में पेश नहीं हुआ और उसका पता नहीं चला, तब अदालत ने उसे आधिकारिक रूप से अपराधी घोषित कर दिया था।गिरफ्तारी के बाद आरोपी को भुवनेश्वर लाया गया और विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।अधिकारियों ने बताया कि आगे की पूछताछ में घोटाले के दायरे और उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की जाएगी, जिन्होंने उसे फरारी के दौरान सहायता दी। यह गिरफ्तारी ओडिशा में वित्तीय धोखाधड़ी और चिटफंड घोटालों के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।एजेंसी ने यह दोहराया है कि वह सभी दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे उन्हें पकड़ने में जितना भी समय ज्यों न लगे। सूत्रों के अनुसार, अब सीबीआई की प्राथमिकता घोटाले से निकाले गए पैसों की बरामदगी और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने पर होगी। मामले की आगे जांच जारी है।

नशे के मकड़जाल में फंस रहा युवा वर्ग

राजगांगपुर १५/०४ (संवाददाता): शहर के युवा नशे के मकड़जाल में फंसकर बर्बादी के कगार पर पहुंच रहे हैं। इससे उनकी सेहत तो खराब हो ही रही है। साथ ही उनका सामाजिक स्तर भी गिरता जा रहा है।

ओडिशा के बुनकरों और बुनाई का उत्सव मनाते हुए-दीपिका हस्तकरघा

राउरकेला १५/०४ (संवाददाता): देश भर में पालित राष्ट्रीय हस्थकरघा दिवस के साथ इस्पात नगरी राउरकेला के हृदयस्थल में परिवर्तन की एक उल्लेखनीय कहानी रची जा रही है—एक ऐसी कहानी जहाँ परम्परा के धागों को सशक्तिकरण और अवसर के ताने-बाने में बुना जा रहा है। इस सबके बीच, राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) द्वारा अपने सीएसआर पहल के तहत स्थापित दीपिका हस्त करघा, एक जीवंत हस्थकरघा बुनाई इकाई है जिसे क्षेत्र के प्रमुख परोपकारी संगठनों में से एक, दीपिका महिला संघति द्वारा देखभाल और प्रतिबद्धता के साथ सँवारा एवं सींचा जा रहा है। दीपिका महिला जागृति संस्थान, सेक्टर-2 के परिसर में स्थित, यह केंद्र अत्याधुनिक हस्थकरघा उपकरणों और सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें प्री-लूम उपकरण, फ्रेम लूम और पिट लूम आदि शामिल हैं। 2 अक्टूबर 2012 में अपने उद्घाटन के बाद से, यह केंद्र आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रहा है-जिनमें से कई के पास कभी शिक्षा या तकनीकी कौशल तक की पहुँच नहीं थी। इन वर्षों में, इन महिलाओं ने, जिनमें से कई ने पहले कभी करघे को हाथ नहीं लगाया था, हस्थकरघा बुनाई की जटिल कला में महारत हासिल कर ली है। धागा लपेटने की मूल बातें सीखने से लेकर जटिल डिज़ाइन वाली सूती और रेशमी साड़ियाँ एवं कपड़े बनाने तक का उनका सफ़र किसी सपने से कम नहीं है।प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक महिला को मासिक वजीफा मिलता है, जिससे उन्हें आत्मविश्वास और क्षमता बढ़ने के साथ-साथ खुद को सहारा देने में मदद मिलती है। दीपिका हस्तकरघा के उत्पाद सेक्टर-5 मार्केट में स्थापित एक समर्पित दुकान %दीपिका हाउस% के साथ-साथ विभिन्न प्रदर्शनियों में भी बेचे जा रहे हैं।राष्ट्रीय हस्थकरघा दिवस के उपलक्ष्य में 7 अगस्त, 2025 को दीपिका हस्तकरघा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीपिका महिला संघती की अध्यक्षा श्रीमती नम्रता वर्मा ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर डीएमएस की सभी उपाध्यक्षाएँ, श्रीमती प्रभाती मिश्र, महाप्रबंधक प्रभारी (सीएसआर), सुश्री मुनमुन मित्रा, उप महाप्रबंधक (सीसआर), श्री टी बी टोप्पो, डीएमएस की सचिव, श्रीमती सारिका कुमार, डीएमएस के शासी निकाय के सदस्य और हस्थकरघा केंद्र के प्रशिक्षु उपस्थित थे। इस अवसर पर एक फैशन शो का आयोजन किया गया जिसमें प्रशिक्षुओं ने हस्तकरघा इकाई में बनी साड़ियों का प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों के बीच हस्थकरघा कपड़े पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। समारोह के उपलक्ष्य में एक केक काटा गया। श्रीमती सारिका कुमार ने कार्यक्रम का सञ्चालन किया द्ध